न्यूज विंडो

'भोपाल स्लाटर हाउस मामला लोगों की आस्था से खिलवाड़'

भोपाल @ पत्रिका. भोपाल के जहांगीराबाद स्थित मॉडर्न स्लॉटर हाउस मामले में कांग्रेस ने गंभीर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप लगाए हैं। बुधवार को पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शासन-प्रशासन को घेरा। साथ ही सरकार से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की। शर्मा ने कहा, यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था, परंपराओं और शासन-प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा है। आरोप लगाया कि इस प्रकरण में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं।

गेहूं खरीदी तंत्र पूरी तरह विफल, किसान हो रहे परेशान : जीतू

भोपाल @ पत्रिका. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में गेहूं खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सरकार का पूरा खरीदी तंत्र विफल हो चुका है और किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गेहूं खरीदी व्यवस्था तत्काल सुचारु की जाए। पटवारी ने कहा, किसान लगातार स्लॉट बुकिंग में दिक्कत झेल रहे हैं, पुनः सत्यापन के संदेश आ रहे हैं, सर्वर धीमा पड़ रहा है, वेबसाइट बंद हो रही है और छोटे किसानों की भी समय पर तुलाई नहीं हो पा रही है। सरकार की लापरवाही का खामियाजा अन्नदाता भुगत रहा है। पटवारी ने कहा भिंड, मुरैना और राजगढ़ जिलों में समर्थम मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान कई फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं।

खाद्य अफसरों की मनमानी छुट्टी पर भड़का संचालनालय

सतना @ पत्रिका. खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग अपने अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर परेशान है। जिलों में हालात ऐसे हैं कि अफसर छुट्टी का आवेदन देकर मुख्यालय से गायब हो जाते हैं जबकि आवेदन स्वीकृति नहीं होती है। लगातार संचालनालय को शिकायतें मिलने लगीं तो आयुक्त खाद्य ने अब सख्ती दिखाई है। आयुक्त ने बिना सक्षम स्वीकृति के अवकाश पर जाने पर रोक तो लगाई ही साथ ही कहा है कि मौजूदा हालातों में जिला आपूर्ति अधिकारियों को अब अवकाश ही स्वीकृत नहीं करें, सिर्फ विशेष स्थिति में दें। आयुक्त ने कहा- भू-राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से एलपीजी, डीजल, पेट्रोल की उपलब्धता की सतत मॉनीटरिंग और गेहूं उपार्जन जैसी चुनौतियों के बीच सक्रियता से कार्य करें।

मध्यप्रदेश में गहराता जा रहा नेता व अफसरों के बीच विवाद

नेता ही नहीं, अफसर भी बेलगाम!

विशेषज्ञ बोले- यह नया चलन, इसकी तह तक कोई नहीं जा रहा

अफसर-नेताओं के बीच नहीं बनने का जनता भुगत रही खामियाजा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. नेताओं व अफसरों के बीच तीखी कहा-सुनी और विवाद का चलन मप्र में गति पकड़ रहा है। पहले आइएएस संजीव श्रीवास्तव और भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का विवाद सुर्खियां बटोर चुका है। हाल में पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का एसडीओपी और मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान का आलीराजपुर जनपद पंचायत सीईओ के साथ सामने आया विवाद कई राज्यों में चर्चा का विषय बना है।

आमतौर पर इन विवादों के लिए नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की राय में यह पूरी तरह सही नहीं है। पिछले कुछ सालों से मप्र में कुछ अफसरों में भी बेलगाम जैसी कार्यप्रणाली दिखी है। कुछ तहसीलदारों द्वारा पिछले रबी सीजन में खाद वितरण के समय किसानों के साथ की गई खुली अभद्रता व मारपीट इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी घटनाओं से न केवल प्रदेश की छवि पर विपरीत असर पड़ा बल्कि आम जनता का नुकसान भी हुआ। आमतौर पर सुलझे हुए अफसर कभी भी उलझते नहीं है, बल्कि उलझनों को बड़े से बड़े संकट की स्थिति में दूर करते हैं। इसका असर आम लोगों पर अधिक दिखता है। अफसर-नेता के बीच जनता पीस रही है।

प्रदेश में अफसर-नेताओं के बीच भिडंत के कई मामले आए

कई बार अफसर की बदजुबानी से भी उपजा विवाद

नेता-अफसरों में विवाद बढ़ने की ये 3 वजह

1. **जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होना:** अंदरखाने यह चर्चा है कि इन दिनों कई नेताओं की ही सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ अफसरों को सीधे बड़े जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है। इस वजह से द्वंद बढ़ रहा है।

2. **प्रभाव कम होना:** पूर्व में नेता व अफसरों के बीच होने वाले विवादों को गंभीरता से लिया जाता था। विवाद के लिए जिम्मेदार की जिम्मेदारी तय होती थी। अब ऐसा कम हो रहा।

3. **जनता का दबाव:** पहले से कम लेकिन अभी भी लोगों की पहुंच जनप्रतिनिधियों तक है। वे समस्या बताकर निराकरण चाहते हैं। हल नहीं निकलने पर संबंधित जनप्रतिनिधि को नजर अंदाज करते हैं या किसी न किसी रूप में गुस्सा जाहिर करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि अफसरों पर गुस्सा निकालते हैं, जिसे आज की अफसरशाही का एक तबका बर्दाश्त करने की बजाए खुद के खिलाफ मान रहा।

विधायक पुत्र और एसडीओपी में विवाद: शिवपुरी के करैरा सीट से विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश की रंगदारी का हालही में मामला सामने आया। बेटे पर केस के बाद विधायक ने अभद्रता की।

विशेषज्ञ बोलें

कई अफसर नेताओं के बंगले पर चक्कर लगाते हैं, जब तक सब कुछ ठीक रहता है तब तक कोई बात सामने नहीं आती। बात बिगड़ने पर आरोप-प्रत्यारोप सामने आते हैं। नेताओं के बंगलों पर जाना छोड़ना होगा।

- विजय दत्त श्रीधर, राजनीतिक

ज्यादातर मामलों में विवाद करने वाले नेता और अफसर दोनों ही जिम्मेदार है। इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है। कमोवेश मप्र में यह स्थिति बढ़ती जा रही है, जो ठीक बात नहीं है।

- महेश श्रीवास्तव, प्रशासनिक

नेता और अफसरों अपने अधिकार जान लें तो विवाद को काफी हद तक टाला जा सकता है। दोनों एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, जिसमें यह भी देखना चाहिए कि संबंधित काम कानूनी दृष्टि से कितना वाजिब है।

- गिरिजाशंकर, प्रशासनिक

बड़े अस्पतालों में दूर-दराज से आने वाले लोग हो रहे परेशान

नियमों में उलझकर दिखावा बनी फ्री शव वाहन सेवा, जिलों तक सीमित दायरा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. सरकार ने मरीजों की मौत हो जाने के बाद उनकी पार्थिव देह आसानी से उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में निःशुल्क शव वाहन सेवा शुरू तो करा दी है लेकिन अधिकांश लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा इस सेवा के संबंध में बनाया गया एक नियम ही इस सेवा में बाधक बन रहा है। दरअसल इस सेवा को जिला स्तर तक ही सीमित रखा गया है। जो शव वाहन जिस जिले में हैं, वे केवल उसी जिले के अंदर पार्थिव शरीर घर तक पहुंचा सकते हैं। जिले के बाहर जाने की अनुमति इन वाहनों को नहीं है। यहां तक कि भोपाल से यदि किसी व्यक्ति को रायसेन पार्थिव शरीर ले जाना है तो यह नियमों के कारण संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को निजी वाहनों के भरोसे होना पड़ता है। बता दें, सीएम डॉ. मोहन यादव ने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई निःशुल्क शव वाहन सेवा का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों के लिए 148 शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। योजना के तहत जिला चिकित्सालयों के लिए दो शव वाहन और जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, उनके लिए चार वाहन दिए गए। निःशुल्क वाहन सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहे इसके लिए पूरे समय वाहन चालक की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।

बड़े शहरों में परेशानी

अधिकांश शव वाहन नियमों में उलझकर खड़े रहते हैं। क्योंकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे प्रदेश के बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेज और एम्स में पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं। दुर्भाग्य से मरीज की मौत हो जाती है तो दूसरे जिले के कारण उन्हें सुविधा ही नहीं मिलती। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस विसंगति को स्वीकार कर सुधार की बात कह रहे हैं।

केवल सरकारी अस्पतालों के लिए सुविधा: इस सेवा से जुड़ा एक और नियम है कि शव वाहन का शासकीय चिकित्सा संस्थानों में मृत्यु पर मिलेगी। ऐसे में यदि कोई गरीब निजी अस्पताल जाएगा तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में बवाल... पुतला दहन के दौरान झड़प, कार्यकर्ता-पुलिसकर्मी झुलसे

छतरपुर@पत्रिका. यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बुधवार को पुतला दहन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी कई नेता झुलस गए। इस बीच अफरा-तफरी मच गई। दरअसल, युकां नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ कई मांगों को लेकर विरोध जता रहे थे। जब कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया, तब टीआइ सतीश सिंह व जवानों से झूमा-झटकी हुई। आग से युकां नेता सहित पुलिस के कई जवान झुलसे। मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा, कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस दबाने का प्रयास करती है, जबकि सत्तादल को छूट दी जाती है।

गेहूं खरीदी केंद्रों में व्यवस्था परखने उतरेंगे मुख्यमंत्री

भोपाल@पत्रिका. सीएम डॉ. मोहन यादव आने वाले दिनों में गेहूं खरीदी केंद्रों का अचानक निरीक्षण करेंगे। यह बात उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत में खुद कही है। वे पूर्व में भी जनता से जुड़े कार्यालयों में पहुंच चुके हैं। असल में गेहूं खरीदी को लेकर किसानों की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में खरीदी केंद्रों का अचानक निरीक्षण करने की बात, व्यवस्थाओं को कहीं न कहीं और मजबूत बनाएगी। बता दें कि अब तक 5 लाख किसानों ने 22.70 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। जबकि 9.83 लाख किसानों ने 60.84 लाख मीट्रिक टन गेहू बेचने के लिए स्लॉट बुक कराया है। उधर किसानों को बेचे गए गेहूं के बदले 3575.11 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कृषि विषयों पर चर्चा की।

अनोखा विरोध

मांगे पूरी कराने तहसीलदार के सामने पटवारियों ने नाक रगड़ी

टीकमगढ़@पत्रिका. टीकमगढ़ में बुधवार को पटवारी संघ के पदाधिकारी बल्देवगढ़ तहसील पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के अध्यक्ष चंद्रभान समारी ने बार-बार ज्ञापन देने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर तहसीलदार अनिल गुप्ता के सामने नाक रगड़कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। दरअसल, जिले की सभी तहसीलो में पटवारियों के 10, 20, 30, 35 वर्ष में लगने वाले समयमान वेतनमान लंबित हैं। वहीं डीए एरियर्स रिश का भुगतान, नए पटवारियों की संविदा अवधि समाप्त कर नियमित करने जैसी मांगे कर रहे हैं।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

अंचलः द्वितीय तल, भारतीय स्टेट बैंक के पास, नयापुरा, कोलार रोड, अकबरपुर, मेन कोलार रोड, भोपाल -462042 फोन : 0755-4249988, 4243700, 4203836

ई-नीलामी विक्रय सूचना

QR CODE FOR SERVICE PROVIDER

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना दिनांक 20.05.2026 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 54) के अंतर्गत बैंक को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि, पंजाब और सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार हमारी शाखा में निम्नलिखित ऋण खातों में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया है, जिन्हें बैंक के बकाया की वसूली के लिए 'जैसा है, जहां है और जैसा है, के आधार पर' बेचने का अधिकार है। बिक्री https://www.Baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा / खाते / ऋणी / जमानतदारों के नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि (रु.) +भविष्य में देय ब्याज एवं अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि	Qr Code For Property Image/video	Qr Code For Property Location
1.	इटारसी शाखा : इटारसी ऋणी/बंधककर्ता: 1. मेसर्स सिहोते ट्रेडर्स उनके पार्टनर्स (i) उमेश सिहोते पुत्र रमेश प्रसाद सिहोते (i) श्री जितेंद्र सिहोते पुत्र रमेश प्रसाद सिहोते 2. श्री विजेंद्र सिहोते पुत्र रमेश प्रसाद जमानतदार-1. श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री नरेंद्र शर्मा	निर्मित मकान के साथ प्लाट स्थित डायवर्टेड खसरा नं. 125,126,128/1,128/2, 128/3, 128/4, एवं 128/5, लेआउट प्लाट नं. 01, क्षेत्रफल- 1600 वर्गफिट, मौजा मेहरगांव, टाउन वार्ड नं. 18, इटारसी, संपत्ति की चतुर्सीमाएं- उत्तर- प्लाट नं. 02, दक्षिण- श्रीमती अलका अग्रवाल की भूमि, पूर्व- अन्य की भूमि, पश्चिम- प्रस्तावित भूमि कब्जे का प्रकार - भौतिक कब्जा	दिनांकः 21.07.2022 ₹ 6,38,270.79 + दिनांक 01.09.2021 से देय ब्याज एवं खर्च	₹ 11,73,000/- / ₹ 1,17,300/- / ₹ 11,730/-		

संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय : 18.05.2026 (सुबह 10.00 से दोपहर 3.00 बजे तक) ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की दिनांक 19.05.2026 दोपहर 6.00 बजे तक

बोलीदाताओं द्वारा ईएमडी को ई-नीलामी पोर्टल अर्थात www.Baanknet.com/ पर उपलब्ध कराए गए अपने वॉलेट में एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।
खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है: , खाते का नाम- एनईएफटी पार्किंग खाता; खाता संख्या- 80215040070003; आईएफएस कोड- PSIB0008021
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi-list & https://www.Baanknet.com देखें
इस नोटिस को नियम 8(6) प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन), नियम 2002 के तहत ऋणियों एवं जमानतदारों (एल/आर) को 15 दिनों की वैधानिक बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जाना चाहिए।
प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क : श्री कुंदन मिश्रा मोबाइल नं. + 91 7896756869

दिनांक : 29.04.2026 स्थान- भोपाल प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नेता प्रतिपक्ष ने आरक्षण पर लगाए आरोप

सरकार ओबीसी वोट चाहती है लेकिन हक नहीं दे रही: सिंघार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बुधवार को कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश में 50% से अधिक आबादी होने के बावजूद सरकार उन्हें अधिकार देने में हिचकिचा रही है। सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग का वोट तो चाहती है, लेकिन उन्हें उनका हक देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी चेहरों को आगे रखकर राजनीति की जा रही है, जबकि उनके अधिकारों को अदालत के पाले में डाल दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट में लंबित मामले में ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा। वहीं निर्मला सप्रे के मामले में भी कोर्ट से न्याय की बात कही। महिला आरक्षण और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर कहा कि महिला आरक्षण पर एक ओर सरकार 2029 के सपने दिखा रही है, वहीं यूसीसी पर बंद कमरे में फैसले ले रहे हैं। सिंघार ने मांग की कि सरकार यह स्पष्ट करे कि दलित-आदिवासी समाज को यूसीसी में शामिल किया जाए।

किसानों का हक अटका

सिंघार ने कहा कि गेहूं खरीदी को लेकर प्रदेश में सर्वर डाउन, स्लॉट गायब और अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हैं। पहले मंडियों में पर्ची कटते ही तुलाई हो जाती थी, लेकिन अब इंटरनेट व्यवस्था के कारण किसानों का हक अटक गया है।

हितग्राहियों के खाते में पहुंचे ₹200 करोड़

भोपाल @ पत्रिका. सामाजिक पेंशन समेत विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत मप्र में दर्ज 33.45 लाख से अधिक हितग्राहियों को 200 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को यह राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की। यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस विश्वास का अंतरण है कि सरकार हर घड़ी जरूरतमंदों के साथ खड़ी है।

कम निवेश में बड़ा बिज़नेस
गाँव का चाय वाला फ्रैंचाइजी

₹12,89,000 की फ्रैंचाइजी मात्र ₹1,98,500+GST 10 वर्षों के लिए

1 वर्ष में 10,000 फ्रैंचाइजी खोलने का लक्ष्य
विशेषताएं -198500 + GST
कंप्लीट रेस्टोरेंट सेटअप (नियम शर्तें लागू)
20+ राज्य

GAANV KA CHAI WALA

गाँव का चाय वाला
TEST THE SIMPLICITY OF THE VILLAGE
Kadak Chai | Desi Swad | Mitti ki Khushboo

मुकेश तिवारी बॉलीवुड अभिनेता (ब्रांड एम्बेसडर)

भारत के गाँव का स्वाद
हमारे रेस्टोरेंट में लजीज पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, कंपलीट फास्ट फूड, ग्राहक को केले के पत्ते, मिट्टी के बर्तन व अन्य पेड़ के पत्तों पर लजीज भोजन परोसा जाएगा। अंकुरित मूंग, मेथी, उड़द, चना व सभी हेल्थ फ्रूट। हेल्दी मिलेट बांस के गिलास में फ्रेश जूस। पेड़ के पत्तों में शुद्ध दूध से बनी स्वादिष्ट आइसक्रीम व सभी टाइप के शेक। मिट्टी के बर्तन में तैयार साउथ इंडियन फूड्स। ग्रामीण परिवेश व गांव की महिलाओं द्वारा हाथ की चक्की से तैयार शुद्ध दालें, शुद्ध मसाले, बेसन व मक्का का आटा।

पंजीकृत कार्यालय :- गांव का चाय वाला MYK एफएमसीजी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम / पोस्ट – नोहटा, तहसील–जबेरा, जिला–दमोह (मध्यप्रदेश)
संपर्क करें- 97999 39669, 82093 63824, 98284 59421, 86197 21337, 70141 57307, 63765 99580